प्रश्न पुस्तिका क्रमांक
Question Booklet Serial No. : 672- 0045747

INTERMEDIATE SENT-UP EXAMINATION – 2026
इन्टरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा – 2026

A

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड
Question Booklet Set Code

POLITICAL SCIENCE (Elective)
राजनीति शास्त्र (ऐच्छिक)

I. A.

विषय कोड :
Subject Code : 322

कुल प्रश्न : 100 + 30 + 8 = 138
Total Questions : 100 + 30 + 8 = 138
(समय : 3 घंटे 15 मिनट)
[Time : 3 Hours 15 Minutes]

कुल मुद्रित पृष्ठ : 24
Total Printed Pages : 24
(पूर्णांक : 100)
[Full Marks : 100]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर-पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

Instructions for the candidates :

1. **Candidate must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.**
2. *Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.*
3. *Figures in the right hand margin indicate full marks.*
4. *15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.*

खण्ड - ब / SECTION - B

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 लघु उत्तरीय हैं । किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें । प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है । **15 × 2 = 30**

Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks. 15 × 2 = 30

1. किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करें ।
   Describe any two fundamental rights.
2. अनुच्छेद 19 की संक्षिप्त व्याख्या करें ।
   Explain Article 19 in brief.
3. प्रस्तावना का महत्व क्या है ?
   What is the importance of Preamble ?
4. अवसर की समानता पर टिप्पणी लिखें ।
   Write a note on equality of opportunity.
5. नीति निदेशक तत्व से आप क्या समझते हैं ?
   What do you understand by Directive Principles ?
6. संविधान की मूल संरचना समझाएँ ।
   Explain the basic structure of the Constitution.
7. किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखें ।
   Write any two fundamental duties.
8. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
   Who appoints the Chief Election Commissioner ?
9. मध्यावधि चुनाव क्या है ?
   What is mid-term election ?
10. सहयोगी संघवाद से आप क्या समझते हैं ?
    What do you understand by Cooperative Federalism ?
11. समवर्ती सूची क्या है ?
    What is Concurrent List ?
12. भारतीय दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ लिखें ।
    Write any two features of Indian party system.
13. आसियान की कोई दो उपलब्धियाँ बताएँ ।
    State any two achievements of ASEAN.
14. सार्क की क्या प्रासंगिकता है ?
    What is the relevance of SAARC ?

A

15. नाम (NAM) का क्या भविष्य है ?
What is the future of NAM ?

16. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन करें ।
Describe the veto power of the President ?

17. प्रश्न काल क्या है ?
What is Question Hour ?

18. प्रधानमंत्री की विधायी शक्तियों पर टिप्पणी लिखें ।
Write a note on the legislative powers of the Prime Minister.

19. मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्ति क्या है ?
What is the executive power of Chief Minister ?

20. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है ?
What is the amendment process of the Constitution of India ?

21. नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखें ।
Write any two functions of Municipal Corporation.

22. नक्सलवाद क्या है ?
What is Naxalism ?

23. क्षेत्रीयता की समस्या के दो कारण बताएँ ।
State any two reasons of the problem of regionalism.

24. बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है ?
What is the role of caste in Bihar politics ?

25. लोकसभा के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख करें ।
Mention any two functions of the Lok Sabha.

26. राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं ?
How are the members of Rajya Sabha elected ?

27. भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' क्या है ?
What is India's 'Neighbourhood First Policy' ?

28. सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है ?
What is collective responsibility ?

29. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है ?
When is the President's rule imposed in a state ?

30. राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति की चर्चा करें ।
Discuss one special power of the Rajya Sabha.

A

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रकार हैं । किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें । प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है । 4 × 5 = 20

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks. 4 × 5 = 20

31. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की विवेचना करें ।

Discuss the importance of Directive Principles of State Policy.

32. मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होती है ?

How are the fundamental rights protected ?

33. चुनाव आयोग के कार्यों को स्पष्ट करें ।

Explain the functions of Election Commission.

34. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करें ।

Discuss the emergency powers of the President.

35. राज्यपाल की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें ।

Critically explain the role of Governor.

36. लोकसभा की शक्ति एवं स्थिति की चर्चा करें ।

Discuss the powers and position of Lok Sabha.

37. भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों पर एक निबन्ध लिखें ।

Write an essay on the determinants of India's foreign policy.

38. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डालें ।

Throw light on the importance of Panchayati Raj institutions.

Bihar Board Class 12 Political Science Sent-Up Exam 2026 – सम्पूर्ण Solutions

नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर सरल हिंदी में तैयार किए गए हैं। उत्तरों को परीक्षा में लिखने योग्य भाषा में रखा गया है।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (1–30):** प्रत्येक उत्तर 2 अंक के अनुसार।
- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (31–38):** प्रत्येक उत्तर 5 अंक के अनुसार।

प्रश्नपत्र में लघु उत्तरीय के 15 और दीर्घ उत्तरीय के 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन तैयारी के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं।

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

प्रश्न 1. किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करें।

उत्तर: भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें से दो प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं:

1. **समानता का अधिकार:** इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
2. **स्वतंत्रता का अधिकार:** इसके अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति, विचार, शांतिपूर्ण सभा और आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त है।

प्रश्न 2. अनुच्छेद 19 की संक्षिप्त व्याख्या करें।

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। इनमें विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, कहीं भी निवास करने तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

प्रश्न 3. प्रस्तावना का क्या महत्व है?

उत्तर: संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं उसकी आत्मा कहलाती है। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को स्थापित करती है।

प्रश्न 4. अवसर की समानता पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: अवसर की समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में जाति, धर्म, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 5. नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36 से 51) में दिए गए हैं। ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने तथा लोककल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

प्रश्न 6. संविधान की मूल संरचना समझाएँ।

उत्तर: संविधान की मूल संरचना से तात्पर्य संविधान की उन महत्वपूर्ण विशेषताओं से है जिन्हें संसद संशोधन करके समाप्त नहीं कर सकती। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन शामिल हैं।

प्रश्न 7. किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखें।

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनमें से दो निम्नलिखित हैं:

1. संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
2. भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना।

प्रश्न 8. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

प्रश्न 9. मध्यावधि चुनाव क्या है?

उत्तर: जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी कारणवश उसे भंग कर दिया जाता है और नए प्रतिनिधियों के चुनाव कराए जाते हैं, तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

प्रश्न 10. सहयोगी संघवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: सहयोगी संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय के आधार पर शासन चलाना। इसमें दोनों सरकारें देश के विकास और जनकल्याण के लिए मिलकर कार्य करती हैं।

प्रश्न 11. समवर्ती सूची क्या है?

उत्तर: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख है। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। शिक्षा, वन, विवाह और श्रम कल्याण इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रश्न 12. भारतीय दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ लिखें।

उत्तर: भारतीय दलीय प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है।
2. भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक दल सक्रिय हैं।

प्रश्न 13. आसियान की कोई दो उपलब्धियाँ बताएँ।

उत्तर: आसियान (ASEAN) की दो प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1. इसने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा दिया है।
2. इसने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रश्न 14. सार्क की क्या प्रासंगिकता है?

उत्तर: सार्क (SAARC) दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना तथा क्षेत्रीय विकास और शांति को प्रोत्साहित करना है।

प्रश्न 15. नाम (NAM) का क्या भविष्य है?

उत्तर: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का भविष्य आज भी महत्वपूर्ण है। यह विकासशील देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने, विश्व शांति स्थापित करने तथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का मंच प्रदान करता है।

प्रश्न 16. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन करें।

उत्तर: राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अर्थ है संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास मुख्यतः तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं:

1. पूर्ण वीटो।
2. निलंबनकारी वीटो।
3. पॉकेट वीटो।

प्रश्न 17. प्रश्नकाल क्या है?

उत्तर: संसद की कार्यवाही के दौरान सामान्यतः पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान सांसद मंत्रियों से सरकार के कार्यों, नीतियों और योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

प्रश्न 18. प्रधानमंत्री की विधायी शक्तियों पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। वह विधायी कार्यक्रम तय करने, महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने की सलाह देने तथा मंत्रियों के माध्यम से विधायी कार्यों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न 19. मुख्यमंत्री की कार्यपालिका शक्ति क्या है?

उत्तर: मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, मंत्रियों के विभागों का बँटवारा करता है, सरकारी नीतियों को लागू करवाता है तथा राज्यपाल को प्रशासन से संबंधित जानकारी देता है।

प्रश्न 20. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान में संशोधन मुख्यतः तीन तरीकों से किया जाता है:

1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा।
2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा।
3. संसद के विशेष बहुमत तथा कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा।

प्रश्न 21. नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखें।

उत्तर: नगर निगम के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. शहर में सफाई, पेयजल और कूड़ा-कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करना।
2. सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना।

प्रश्न 22. नक्सलवाद क्या है?

उत्तर: नक्सलवाद भारत में एक उग्र वामपंथी आंदोलन है, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी।

प्रश्न 23. क्षेत्रीयता की समस्या के दो कारण बताएँ।

उत्तर: क्षेत्रीयता की समस्या के दो प्रमुख कारण हैं:

1. विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की असमानता।
2. भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लोगों में अलगाव की भावना।

प्रश्न 24. बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है?

उत्तर: बिहार की राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति बनाते समय जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। जाति मतदाताओं के मतदान व्यवहार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित करती है।

प्रश्न 25. लोकसभा के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख करें।

उत्तर: लोकसभा के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. कानूनों का निर्माण करना और विधेयकों को पारित करना।
2. सरकार पर नियंत्रण रखना तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाना।

प्रश्न 26. राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं?

उत्तर: राज्यसभा के अधिकांश सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं।

प्रश्न 27. भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' क्या है?

उत्तर: नेबरहुड फर्स्ट नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, व्यापार, सुरक्षा, परिवहन और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

प्रश्न 28. सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है?

उत्तर: सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

प्रश्न 29. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है?

उत्तर: जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ होती है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।

प्रश्न 30. राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति की चर्चा करें।

उत्तर: राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत विशेष शक्ति प्राप्त है। यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

खंड – C : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 अंक)

प्रश्न 31. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की विवेचना करें।

उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक लोककल्याणकारी राज्य बनाना है।

इनका महत्व निम्नलिखित है:

1. **सामाजिक न्याय:** समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं।
2. **आर्थिक समानता:** सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने पर बल देते हैं।
3. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य:** सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं।
4. **ग्राम पंचायतों का विकास:** ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाने पर बल देते हैं।
5. **अंतरराष्ट्रीय शांति:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

निष्कर्ष: नीति निर्देशक तत्व सरकार को जनकल्याणकारी नीतियाँ बनाने की दिशा प्रदान करते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रश्न 32. मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होती है?

उत्तर: भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

1. **न्यायपालिका की स्वतंत्रता:** भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
2. **सर्वोच्च न्यायालय:** अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
3. **उच्च न्यायालय:** अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
4. **रिट जारी करना:** न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसी पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं।
5. **न्यायिक समीक्षा:** न्यायालय संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

निष्कर्ष: मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित रखती है।

प्रश्न 33. निर्वाचन आयोग के कार्यों को स्पष्ट करें।

उत्तर: भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. **चुनाव का संचालन:** लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना।
2. **मतदाता सूची:** मतदाता सूची तैयार करवाना और उसमें आवश्यक संशोधन करना।
3. **चुनाव कार्यक्रम:** चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा करना।
4. **राजनीतिक दलों को मान्यता:** राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिह्न आवंटित करना।
5. **आदर्श आचार संहिता:** चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करवाना।
6. **चुनाव पर नियंत्रण:** चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना।

निष्कर्ष: निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 34. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करें।

उत्तर: भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश में संकट की स्थिति से निपटने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं:

1. **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):** जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
2. **राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356):** जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
3. **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):** जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा होता है, तब वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रश्न 35. राज्यपाल की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

उत्तर: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

राज्यपाल के प्रमुख कार्य एवं भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य:** राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
2. **विधायी कार्य:** राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग कर सकता है।
3. **विधेयकों पर स्वीकृति:** राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
4. **वित्तीय कार्य:** राज्यपाल की अनुमति से राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
5. **विवेकाधीन शक्तियाँ:** विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है, जैसे त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति।

आलोचना: कई बार राज्यपाल पर केंद्र सरकार के पक्ष में कार्य करने तथा राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के आरोप लगते हैं।

निष्कर्ष: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। उसे निष्पक्ष रहकर संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए।

प्रश्न 36. लोकसभा की शक्ति एवं स्थिति की चर्चा करें।

उत्तर: लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **विधायी शक्ति:** लोकसभा कानून बनाने और विधेयकों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2. **वित्तीय शक्ति:** धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण:** लोकसभा प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव और चर्चा के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है।
4. **निर्वाचन संबंधी शक्ति:** लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
5. **संविधान संशोधन:** लोकसभा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में भाग लेती है।
6. **न्यायिक शक्ति:** लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है।

निष्कर्ष: लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।

प्रश्न 37. भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों पर एक निबंध लिखें।

उत्तर: विदेश नीति से तात्पर्य उन सिद्धांतों और नीतियों से है जिनके आधार पर कोई देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना है।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं:

1. **भौगोलिक स्थिति:** भारत की भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
2. **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत:** भारत की प्राचीन संस्कृति, शांति और अहिंसा के सिद्धांत विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।
3. **राष्ट्रीय सुरक्षा:** देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करना विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
4. **आर्थिक विकास:** व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना।
5. **गुटनिरपेक्षता:** भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।
6. **विश्व शांति:** भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है।
7. **राष्ट्रीय हित:** भारत अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष: भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों, स्वतंत्र निर्णय, विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।

प्रश्न 38. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डालें।

उत्तर: पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य गाँवों के लोगों को स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में भागीदारी देना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

पंचायती राज संस्थाओं का महत्व निम्नलिखित है:

1. **स्थानीय स्वशासन:** गाँव के लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं।
2. **लोकतंत्र को मजबूत बनाना:** इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं और लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।
3. **ग्रामीण विकास:** गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विकास होता है।
4. **महिलाओं की भागीदारी:** पंचायतों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।
5. **सामाजिक न्याय:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
6. **जनभागीदारी:** ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण लोग विकास योजनाओं में भाग लेते हैं।

पंचायती राज के तीन स्तर:

1. ग्राम पंचायत – ग्राम स्तर पर।
2. पंचायत समिति – प्रखंड स्तर पर।
3. जिला परिषद – जिला स्तर पर।

निष्कर्ष: पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।